अमृत वाणी

गरीबों के समान विनम्र अमीर और अमीरों के समान उदार गरीब ईश्वर के प्रिय पात्र होते हैं।
–शेख सादी,

रखरखाव के प्रति उदासीनता एक गलत परंपरा

शासकीय कामकाज में रखरखाव के प्रति उदासीनता एक गलत पंरपरा बनती जा रही है। चाहे कोई निर्मित भवन हो या संस्था, सड़क हो अथवा पुल या फिर कोई पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थल ही क्यों न हो, एक बार बन जाने के बाद उनके रखरखाव के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यही वजह है कि लाखों करोड़ों के व्यय से निर्मित ये सारे निर्माण कार्य क्रमशः कमजोर होते होते जर्जर स्थिति में पहुंच जाते है और इन तमाम उदासीनताओं और लापरवाहियों का खामियाजा उन लोगों को चुकाना पड़ता है जो किसी भी तरह से इनके जिम्मेदार नहीं है। चाहे गड्ढेनुमा सड़कों पर से गिरते पड़ते चलना हो अथवा बरसात में टपकते छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करना, नमीयुक्त घरों में रहना हो या फिर टूटे फूटे भवनों में संस्था का संचालन करना अधिकतर शासकीय निर्माणों की ऐसी ही दुर्दशा होती है क्योंकि उनके रखरखाव पर समय रहते कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। जब हालात पूरी तरह बिगड़ जाती है। जर्जर भवन धसने की स्थिति में आ जाती है, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है या फिर कुछ बुरी तरह उजड़ जाता है और चारों और से शिकायतों और आलोचनाओं का अंबार शुरू होता है तब कहीं बड़ी मुश्किल से प्रशासन नींद से जागता है और फिर सुधार की कुछ पहल होती है। नतीजा यह कि समय पर किया जाने वाला रखरखाव कार्य जिस व्यय से हो सकता था वह अब उससे कई गुणा अधिक व्यय पर होता है। यह रकम भी तो अंततः जनता की गाढ़ी कमाई से ही वसूली जानी होती है।

चिंता की बात यह कि रखरखाव की ऐसी उदासीनता के कारण कई संस्थान अपनी उपयोगिता और सार्थकता ही खो देते है जिससे शासन को नुकसान तो होता ही है आम लोगों को भी कई बार अनेक लाभ से वंचित होना पड़ता है।

उदाहरण के लिए करोड़ों रूपये के व्यय से नगर सीमा में स्थित आसना ग्राम में वन विभाग द्वारा निर्मित संग्रहालय और आसना पार्क की दशा को देखे। इस संग्रहालय में वनोषधियों के साथ साथ बस्तर के वनवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विलुप्त हो रही वस्तुओं को भी सजाया गया है मगर अब यह संग्रहालय वीरान पड़ा हुआ है। वजह यह है कि पूर्व में इससे लगे आसना पार्क की काफी रौनक हुआ करती थी। वहां वनोषधियों के रोपण के साथ व्यापक संख्या में मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे जिससे बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचा करते थे और संग्रहालय में भी चहल पहल बनी रहती थी। वनोषधियों की खरीददारी से लेकर लोग पार्क का भरपूर मजा लेते थे लेकिन बदकिस्मती से इस पार्क की नियति भी अन्य शासकीय निर्माणों से अलग नहीं रह पाई और रखरखाव के प्रति उदासीनता ने क्रमश इसका आकर्षण समाप्त कर दिया। अतः अब न लोग पार्क जाने में कोई रूचि रखते है न संग्रहालय। दोनों ही वीरान पड़े अपनी हालत पर आंसू बहा रहे है।

समझ में नहीं आता कि ऐसी विभागीय उदासीनता की वजह क्या है। कहा जा रहा है कि वन विभाग शीघ्र ही आसना पार्क को सुधारेगा। मगर हर चीज को इस तरह समाप्त कर फिर से पुनर्निर्माण करने का क्या मतलब। यही काम पहले करके उसके आकर्षण और अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है। इससे जहां शासन के लाखों के व्यय को बचाया जा सकता है वहीं संस्था के स्वरूप और लोगों के जुड़ाव को भंग होने से भी बचाया जा सकता है।

राज काज

सट्टा बाज़ार की हैरानी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की खामोशी ने जहां राजनीतिक पंडितों और भविष्यवक्ताओं की बोलती बंद कर दी है तो वहीं सट्टा बाजार को भी हैरानी में डाल दिया है। दरअसल इन राज्यों में मतदान से पहले तक सट्टा बाजार कभी भाजपा को तो कभी कांग्रेस को बढ़त दिलाता आया हैए लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्थिति दरअसल क्लीयर ही नहीं है कि किस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है या कौन बुरी तरह हार रही है। यह वजह है कि राजस्थान चुनाव में मतदान से पहले तक कांग्रेस को 130 से 140 सीट दिलवा रहा सट्टा बाजार मतदान के दिन अचानक 107 से 115 सीटों तक आ गया और इसी के साथ भाजपा को बढ़त दिखाता नजर आया। यह देख अब चुनाव में लगातार बारीक नजर रखने वाले कह रहे हैं कि पंडितों और भविष्यवक्ताओं के साथ ही साथ सट्टा बाजार भी भ्रमित है क्योंकि इस बार मतदाता पूरी तरह मौन रहा है और उसने बहुत ही समझदारी से अपना फैसला सुनाया हैए अब मतगणना के बाद असली तस्वीर सामने आ सकेगी।

भाजपा सांसद सावित्री फुले का इस्तीफा

राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने जिस तेजी से ऊंचाइयां छूई हैं उतनी ही तेजी से वह गर्त में जाती दिख रही है। यह बात अगर किसी विरोधी ने कही होती तो कोई नहीं मानताए बल्कि पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने इस तरह की बातें करना शुरु कर दी हैं। चूंकि साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं इसलिए इसे खासतौर पर तवज्जोह दी जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से खबर है कि भाजपा सांसद सावित्री फुले ने पार्टी और मोदी सरकार की नीतियों से नाराज होकर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और लोकसभा में वो बनी रहेंगी। इससे भी राजनीति गर्मा गई है। सांसद सावित्री फुले का कहना है कि श्मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दियाए लेकिन कार्यकाल पूरा होने तक लोस की सदस्यता नहीं छोड़ूंगी।श् सांसद फुले का मानना है कि सरकार ने जिस तरह से प्रतिमाएं लगाने में फिजूलखर्ची की है और देश में अराजकता का माहौल बनता गया है उससे वो खासी दुखी हैंए इसलिए उन्हें इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है। वहीं राजनीतिज्ञों का कहना है कि अब इस तरह के और भी सांसद पार्टी छोड़ बड़ा झटका दे सकते हैंए क्योंकि अंदर ही अंदर नाराजगी बहुत बढ़ चुकी है।

क्या चुनाव, चुनाव हैं या प्रबंधन

चुनाव पहले समाज द्वारा जो प्रतिष्ठित ध्योग्य होता था उसे स्वयं लोग चुनते थे पर आज ताकतवर असामाजिक व्यक्ति समाज में आकर कहता हैं की मैं अब तुम्हारा नेता हूँ। इसकी शुरुआत उस समय से शुरू हुई जबसे इन पदों पर आरूढ़ नेताओं को लाभ मिलना शुरू हुआ। पहले नेतागिरी यानी अपना पैसा खरच करो और कभी भी लाभ का सौदा नहीं रहा। ना उनको अपना नाम प्रतिष्ठा की चिंता रहती थी। कारण काम करेंगे तो नाम होगा ही। पर जबसे पैसा ध्भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ और पद प्रतिष्ठा के साथ गुंडागर्दी का प्रभाव होने से राजनीती की और झुकाव होना शुरू हो गया और विधायक ध्सांसद ध्मंत्री ध्मुख्य मंत्री ध्प्रधान मंत्री से लेकर सरपंच आदि को जो चस्का लगा की वे अब नरभक्षी शेर हो गए। जैसे ही चुनांव जीते ही सबसे पहले समाज की बेरोजगारी ख़तम और उनकी गरीबी हटना शुरू हो जाती हैं और उनका विकास दिन दूना होने लगता हैए चुनाव में करोड़ों रूपए खरच करना मामूली बात हैं और उसके बाद चुनाव में प्रबंधन करना सबसे प्रमुख होता हैं।

ईश्वर के आभाव में प्रजा में मास्त्य न्याय प्रचलित हो जाता हैं इसिलए दण्डधर की आवश्यकता होती हैं।

दंड भीत्या ही लोकोयं पन्थम नानुधावत्ति !

युक्त दण्डं धारस्तस्मान पर्थिवाहः प्रथविनं जयेत!! आदिपुराण 16-253, जब संग्रह और लोभ की प्रवत्ति बढ़ती हैं तो संघर्ष की उतपत्ति बढ़ती होती हैं। यह संघर्ष ही चिंता और दीनता का कारण हैं। जब समाज में सभी व्यक्ति शक्ति के अनुसार कार्य और आवश्यकतानुसार पुरुस्कार प्राप्त करते हैं तो संघर्ष नहीं होता और न संचय की प्रवत्ति उतपन्न होती हैं। शारीरिक दोष का कारण असंयम और अनियंत्रित प्रवत्तियाँ हैं। पागलपन और उन्माद का मनोवैज्ञानिक कारण असंतोष मानाहैं

आज सब पार्टियां शासन और सेवा के लिए संघर्षरत हैं और एक दूसरे को सहयोग नहीं देते हैं। स्वदुखे निर्घृणारम्भाः पर दुःखेषु दुःखिताः ! निष्प्रेक्षं पराथ्रेशुः !

और अपने दुःख और कष्ट को दूर करने का प्रतिकार न कर दूसरे के दुःख को दूर करने के लिए प्रयत्नशीलहोना ही सहयोग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। पर आज सब अपना हित सर्वोपरि मानते हैं। और दूसरे का नामोनिशान मिटाने तुले हैं। जब तक सत्ता में पक्ष और विपक्ष न होगा तब तक शासन नहीं चलेगा। क्या कोई भी पक्षी एक पंख से उड़ सकता हैं।

आज स्वयं मुख्य मंत्री कह रहे हैं की चुनाव आयोग बहुत मानवीयता का प्रदर्शन करता हैं और दूसरी ओर चुनाव जीतने किस प्रकार के कितने हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। इससे लगता हैं की चुनाव इस समय प्रबंधन पर जुड़ा हुआ हैं। आज चुनाव का पूरा खेल शुरू से आखिरी तक प्रबधन से जुड़ा हुआ हैं। चुनाव में धांधली का होना आम बात हैं और सत्ता धारी अपने मुकाम को पाने किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस चनाव में विकास की जगह व्यक्तिगत हमले किये गए। ऐसा लगता हैं की प्रदेश विकसित हो चूका हैं और अब सबको मलाई खाना हैं।

चुनाव परिणाम हकीकत सामने लाएगा। पर वर्तमान में वह ही जीतेगा जिसका प्रबधन सबसे बढ़िया और प्रबधित होगा। यदि यह सब होता रहेगा तो चुनाव कराने की अब जरुरत नहीं हैं कारण निष्पक्ष न होना ही चुनाव का महत्वहीन होना हैं।

डॉ. अरविन्द जैन
(ये लेखक के अपने विचार है)

बेरोजगारी उत्तराखंड की ज्वलंत समस्या

प्राकृतिक अपार सम्पदा व सौंदर्य से अच्छादित उत्तराखंड की आज सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या रोजगार पाने की है जहां एक आकड़े के मुताबिक 9 लाख बेरोजगार रोजगार के लिये सड़क पर भटक रहे है। जिसमें देहरादून रोजगार कार्यालय के आकड़े ये बता रहे है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी के मामलें में महिलाओं की संख्या पुरूषों की संख्या से कहीं ज्यादा है। समय . समय पर उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने बेरोजगारी को और ज्यादा बढ़ा दिया है जिससे यहां पलायन की स्थिति बनती जा रही है। समय . समय पर यहां की सरकारें भी बदलती रही पर आज तक इस दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं हो पाये है। इस राज्य की वर्तमान सरकार बेरोजगारी दूर करने की दिशा में स्वरोजगार को एक बेहतर उपाय बता रही है पर केवल स्वरोजगार से ही इस ज्वलंत समस्या का समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार युवा उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सड़क पर उतर आये है। जो वर्तमान सरकार की नीतियों को बेरोजगारी दूर करने की दिशा में एकमात्र छलवा बता रहे है। इस राज्य के बेरोजगार युवको का कहना है कि सरकार खाली पड़े पदों को भर नहीं रहीं है और जिनकी विज्ञपतियां निकली हैए उसकी परीक्षाएं आयोजित नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना केवल दिखावा मात्र है जिससे यहां की बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या का निदान कतई संभव नहीं।

यहां उद्योग की कमी है और यहां का भौगालिक परिवेश उबड़ . खाबड़ होने के कारण खेती हो पाना संभव नहीं। यह पूरा प्रदेश पहाड़ों एघाटियों नदियोंए तालाब एवं झीलों से भरापूरा है। बाढ़ की आई आपदा इस प्रदेश के हालात को और बिगाड़ देती है। जहां भूस्खलन एवं भूकंप की घटनाएं भी आम जनजीवन को संकट में बराबर डाले रहती है। प्रदेश की सरकारें बदलती रही पर बेरोजगारी निदान के ठोस उपाय आज तक नहीं हो पाये जिससे यहां पलायन की स्थिति बनी हुई है। इसके लिये वहां का विपक्ष कांग्रेस एवं भाजपा दोनों को जिम्मेवार मानता है। ऐसा नहीं कि इस राज्य में रोजगार की कोई संभावनाएं नहीं पर इस दिशा में आने वाली किसी भी पार्टी की सरकार ने सकरात्मक कदम उठाने के वजाय एक दूसरे पर आरोप लगाती रही। चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियां रोजगार देने की नई . नई योजनाएं लाने की घोषणएं तो करती है पर सत्ता में आते ही सारी योजनाएं कागजी बनकर रह जाती है। जिससे आज तक इस प्रदेश में बेराजगारी की समस्याएं लगातार बड़ती ही जा रही है। एक आकड़े के मुताबिक आज से 18 वर्ष पूर्व जब राज्य की स्थापना हुईए बेरोजगारों की संख्या 3 लाख के आस . पास थी जो अब यह बढ़कर 10 लाख के आस . पास पहुंच गई। इस तरह के हालात यदि बने रहे जहां प्रति वर्ष एक लाख युवा बेराजगार की सूची में शामिल होते जा रहे हैए बेरोजगारों की एक ऐसी लम्बी फौज प्रदेश में खड़ी हो जायेगी जो किसी भी सरकार के लिये मुसीबत बन सकती है जिसका समाधान करना आसान नहीं रह जायेगा। केवल कागजी योजनाएं इस ज्वलंत समस्या का निदान नहीं हो सकती। आज वर्तमान सरकार की इस दिशा में चल रही तमाम योजनाएं स्वरोजगार के नाम बेरोजगारी को और बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओ में सरकारी कोष से काफी धन कर्ज के रूप में दिया तो जा रहा पर इसका कितना उपयोग सही दिशा में हो रहा है ए इसका कोई निरीक्षण नहीं। जिससे आने वाले समय में वीआरएस की तरह विभिन्न योजनाओं के तहत बेरोजगार युवाओं को लुभाने की दिशा में कर्ज रूप में दी जा रही सौगात नये रोजगार सृजित करने के बजाय बेराजगारी एक नया पैमाना खड़ कर सकती है। जिससे इस प्रदेश से पलायन की स्थिति पहले से भी ज्यदा हो सकती है।

यह प्रदेश मंदिरों एवं प्राकृतिक छटा से अच्छादित रंग . विरंगी दृश्य से भरपूर घाटियों का मनोरम स्थल है जहां प्रतिवर्ष लाखों सैलानी एवं धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोग लगातार आते रहते है। इनके लिये सरकार प्रदेश में जगह . जगह बेहतर पर्यटन केन्द्र खोलकर बेरोजगारो को नियमित रोजगार देने का सुअवसर उपलब्ध करा सकती है। इस प्रदेश में मार्ग की भी ज्वलंत समस्याएं है जिसे सही कर उद्यमियों को नये उद्योग लगाने की दिशा में प्रेरित कर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या बाढएभूकंप एवं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का है जिसका सही हल निकालकर रोजगार देने के संसाधन उद्योग लगाने की संभावनाएं बनाई जा सकती है। जिससे प्रदेश में बेराजगारी की ज्वलंत समस्याएं दूर कर पलायन को रोका जा सकता है। आज भी लोग अपने प्रदेशए अपनी मिट्टीए अपने गांव से बहुत प्यार करते है जिसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते पर पेट के लिये सब कुछ नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है। यदि प्रदेश की सरकार सही मायने में बेरोजगारी दूर करने के सकरात्मक प्रयास करेगी तो इस प्रदेश में अन्य प्रदेश से रोजगार उपलब्ध कराने की बहुत संभावनाएं है जिसपर सच्चे मन से कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश में धारचूला और मुनस्यारी जैसे अनेक स्थल है जहां के पूर्वजों से कालीनएकंबलए उनी वस्त्र बनाने के हुनर मिले है जिन्हें घरेलू उद्योग में विकसित कर रोजगार के अवसर दिये जा सकते है। पहाड़ों पर अनेक जडी बुटियां उपलब्ध है जिनका प्रयोग दवाई कंपनियां खोलकर किया जा सकता है।प्रदेश के उबड़ . खाबड़ जमीन को समतल बनाकर उद्योग एवं कृषि लायक बनाया जा सकता है। इस तरह प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाश कर प्रदेश को रोजगार पाने जैसी ज्वलंत समस्याओं से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

डॉ. भरत मिश्र प्राची
(ये लेखक के अपने विचार है)

मिशेल रामबाण है, भाजपा का

अगस्ता.वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों के सौदे में बिचौलिए का धंधा करनेवाले क्रिश्चियन मिशेल को आखिरकार हमारी सरकार ने धर दबोचा है। वह बधाई की पात्र है। 3000 करोड़ के इस सौदे में लगभग 300 करोड़ रुण् की रिश्वत बांटनेवाले इस दलाल को दुबई से पकड़कर अब दिल्ली ले आया गया है। जांच ब्यूरो के अधिकारी इससे अब सारी सच्चाई उगलवाएंगे। फौज के लिए खरीदे गए हेलिकॉप्टरों के सौदे में किस नेता और किस अफसर को कितने रुण् खिलाए गए हैं, ये तथ्य अब इस ब्रिटिश नागरिक मिशेल से उगलवाए जाएंगे। इसके पहले उक्त कंपनी के जो अफसर पकड़े गए थे, उनकी डायरियों से कुछ नाम उजागर हुए हैं। उन नामों को सोनिया गांधी के परिवार से जोड़ा गया था। हमारी फौज के एक बड़े अफसर पर भी रिश्वतखोरी के आरोप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में यह जबर्दस्त हथियार आ गया है। सोनिया गांधी परिवार के विरुद्ध पहले ही ष्नेशनल हेरल्डष् के मामले में आयकर विभाग जांच कर रहा है। अब मोदी ने सोनिया परिवार की तरफ अपनी चुनाव.सभा में नाम लेकर भी इशारा किया है। हो सकता है कि मिशेल जो भी सच उगले, वह कांग्रेस के गले की फांस बन जाए। यदि वह बोफोर्स की तरह सोनिया परिवार को अदालत में अपराधी सिद्ध न कर पाए तो भी चुनाव के अगले छह सात माह में भाजपा के लिए वह रामबाण सिद्ध हो सकता है। हमारे प्रचारमंत्री इतने तीर चलाएंगे कि कांग्रेस का महागठबंधन चूर.चूर हो सकता है। कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने में हर पार्टी सकुचाएगी। भाजपा यह दावा भी कर सकती है कि जब उसने मिशेल.जैसे ब्रिटिश नागरिक को अपने पंजे में फसा लिया तो विजय माल्या, नीरव मोदी और चोकसे वगैरह तो अपने ही खेत की मूली हैं। उसका भ्रष्टाचार.विरोधी चेहरा देश के मतदाताओं को उसके प्रति उत्साह से भर सकता है। उसने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत.सी पहल की हैं। उसमें से कइयों ने तो शीर्षासन कर दिए और कइयों के सुपरिणाम पर्याप्त ठोस और सगुण नहीं हैं। ऐसे में इस तरह की निषेधात्मक नौटंकियां ही अपनी डगमगाती नाव का सहारा बन सकती हैं। इनमें अयोध्या में राममंदिर का निर्माण भी एक जबर्दस्त पैंतरा है। अगस्ता.वेस्टलैंड का मामला रेफ्ल.सौदे को भी मंच के नीचे ढकेल देगा। लेकिन यह न भूलें कि दिल्ली में यदि दूसरी कोई सरकार आ गई तो उसके हाथ में रेफ्ल का ब्रह्मास्त्र होगा। भ्रष्टाचार तो लोकतांत्रिक सरकारों की प्राणवायु है। उसके बिना वे जिंदा रह ही नहीं सकतीं।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक
(ये लेखक के अपने विचार है)

अनियन्त्रित राजनीति- लोकतन्त्र का महल खोखली चुनावी नींव पर

यह एक चिंतनीय कटु सत्य है कि आज भारतीय लोकतंत्र का महल खोखली चुनावी नींव पर खड़ा है और अनियंत्रित राजनीति की दीमक उस नींव को इसी तरह खोखली करती रही तो यह लोकतंत्र का महल किसी भी दिन जमींदो हो सकता है इस नींव ने अपने राजनीतिक आकाओं से कई बार ऐसा न करने की गुहार लगाई किंतु नींव की गुहार कोई सुनने को तैयार नहीं है और देश के अन्य संवैधानिक इमारतों की तरह लोकतंत्र के इस महल की नींव भी लगातार खोखली की जा रही है और देश के लोकतंत्र की किसी को भी चिंता नहीं है।

यह केवल एक दिखावा भर है कि देश का चुनाव आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष है और वह बहुत ईमानदारी से अपना महान उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि हर मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कर्तव्यों व दायित्वों के ईमानदारी व निष्पक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए छटपटाता है और उसके इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर सत्तारूढ़ राजनेताओं द्वारा धूल डाल दी जाती है।

इसका ताजा उदाहरण चुनाव आयोग के निवृत्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत हैए जिन्होंने खुले रूप में पाँच राज्य विधानसभाओं के चुनावों में कालेधन के दुरूपयोग का आरोप लगाया साथ ही शराब के दखल के प्रति भी चिंता व्यक्त की। चुनाव आयोग ने मतदान के पूर्व अकेले मध्यप्रदेश से सौ करोड़ से अधिक मूल्य की शराब व अन्य सामान जब्त किया जिसका दुरूपयोग मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए होने वाला था। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव 2013 के समय केवल 19 करोड़ का सामान पकड़ाया था इस बार पकड़ी गई अवैध शराब की मात्रा करीब छः लाख लीटर है। इस सत्यता से दुरूखी श्री रावत ने रानीतिक दलों को मिलने वाली चंदे की दौलत और उनके खर्च की सीमा भी तय होना चाहिए चुनाव में कालेधन के उपयोग पर भी श्री रावत ने काफी चिंता व्यक्त की थी।

किंतु वास्तविकता यह है कि राजनीति के नक्कारखाने में चुनाव आयोग प्रमुख की तूती सी आवाज को सुनता कौन हैए यदि यही चलन आगे भी चलता रहा तो देश के सभी संवैधानिक संगठनों को अपने अधिकार, दायित्व व कर्तव्य भूलकर सत्ताधीशों के नियंत्रण में रहना पड़ेगा और सत्ताधारी संगठन ही लोकतंत्र के मालिक बनकर बैठ जाऐंगे।

सबसे बड़े खेद और चिंता की बात तो यह है कि अब दिनोंदिन सत्ता के सिंहासन पर दीर्घजीवी होने के सपने देखें जाने लगे हैए फिर इसके लिए चाहे इन्हें अपना ईमानए वाणी, चरित्र और नैतिकता का त्याग क्यों न करना पड़े। इसीलिए आज.कल चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं के हितों या कल्याण की बात नहीं की जाती उनकी जगह प्रतिपक्षी दलों को गालियाँ देने की कवायदें की जाती है। इसी कारण अब चुनावों में घोषणा.पत्र केवल और केवल दिखावे की वस्तु बनकर रह गए है न उन पर चुनाव जीतने और सत्ता प्राप्त करने के बाद अमल करने पर ध्यान दिया जाता है और न ही उनका कोई महत्व ही प्रतिपादित किया जाता हैए घोषणा.पत्र इसीलिए श्जुमलों का पुलिंदाश् बनकर रह जाते हैए और चूंकि सत्ता प्राप्ति के बाद चुनावी वादों पर कोई अमल तो करना नहीं है इसलिए घोषणा.पत्र तैयार करते समय उन्हें ष्लुभावनेष् बनाने के चक्कर में उनकी पूर्ति में खर्च होने वाली राशि या धन की भी कोई चिंता नहीं की जातीए जिसका ताजा उदाहरण सत्ता प्राप्ति के दस दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा है जिस पर मध्यप्रदेश में पचास हजार करोड़ की राशि खर्च होना है उस प्रदेश में जहां की सरकार पहले से ही करीब दो लाख करोड़ के कर्ज में दबी हुई है और जहां तक चुनाव पर खर्च होने वाली राशि का सवाल हैए उसका कोई हिसाब ही नही है फिलहाल पांच राज्यों में हो रहे विधानसभाओं के चुनावों पर सत्रह हजार करोड़ के खर्च का अनुमान है। चूंकि चुनाव आयोग का किसी को भय नहीं हैए इसलिए उसकी कार्यवाही की चिंता भी किसी को भी नहीं है। इस तरह कुल मिलाकर अब लोकतंत्र पर राजनीतिक सत्ता तंत्र पूरी तरह हावी हो चुका है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब सिर्फ न्यायपालिका पर ही जनविश्वास कायम है और उसी पर सब की नजर है।

ओमप्रकाश मेहता
(ये लेखक के अपने विचार है)